महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम - 695 001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM-695 001

P19/IV/DRSSA/13 **06.06.2024**

To,

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Sanction of various allowances/facilities to Bihar Judicial Service Officers, in the light of Order dated 04.01.2024 passed by the Honourable Supreme Court, New Delhi after the recommendation of the Second National Judicial Pay commission-reg.

Ref: **1.** SSA No. Pen-9-89 dated 15.04.2024 received from the office of the Principal Accountant General (A&E), Bihar
2. Government Resolution No. 3A-3-Allowance-01/2024-2140/Vi. Patna dated 28.02.2024, Government of Bihar, Department of Finance.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the office of the Principal Accountant General (A&E), Bihar, regarding the Sanction of various allowances/facilities to Bihar Judicial Service Officers, in the light of Order dated 04.01.2024 passed by the Honourable Supreme Court, New Delhi after the recommendation of the Second National Judicial Pay commission. The same is being placed in the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, **under pension – download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners"**. A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Encl.: As stated above.

Yours faithfully

Senior Accounts Officer

Copy to: -

1. The Director of Treasuries
   Thiruvananthapuram

2. The Office of the Principal Accountant General (A&E)
   Bihar, Veerchand Patel Path,
   Patna, Bihar – 800 001
   - For information only.

Senior Accounts Officer

ई-मेल/Email : agaekerala@cag.gov.in फेक्स/Fax: 0471-2330242 दूरभाष/Telephone: 0471-2776100
वेबसाइट/Website: http://www.agker.cag.gov.in

P19 | IV | DRSSA | Inw | 13
23/4/24

IV, DRSSA

P19
19048
22/4/24

दूरभाष/Telephone-2223251
2225766, 2224812

फैक्स /Fax – 0612-2221056

तार
Tele | Gram : ACCOUNTS

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

No. / संख्या :- Pen-9-89

Date: / दिनांक:- 15/04/2024

To,

The

1	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500004
2	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon, Beltola, Guwahati	781029
4	Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi	834002
5	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. Of Goa, Director of Accounts, pension Section, Panji, Goa	403101
6	Accountant General (A&E), Chhatisgrah, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafidih, Raipur	492009
7	Accountant General (A&E),, Gujarat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8	Accountant General (A&E), Harayana, Lekhabhawan, Plot No. 4&5, Sector-33-B, Chandigrah	160047
9	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himanchal Pradesh , Gorton Castle Building, Shmila	171003
10	Pr. Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground , Srinagar	190009
11	Pr. Accountant General (A&E),Karnatka, residency Parm Road, Post Box No.5 Bangalore	560001
12	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh , Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14	Pr, Accountant General (A&E), Maharashtra , 2nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karv, Mumbai	400020
15	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line. Nagpur	440001
16	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17	Accountant General (A&E), Meghlalya, Shilong	793001

18	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Buildignh, Dinthar, Aizawl	796001
19	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Nagaland Kohima	797001
20	Accountant General (A&E), Orissa, Bhuneshwar	751001
21	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigrah, Sector-17E, Chandigarh	160017
22	Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhawagan Das Road, Jaipur	302005
23	Sr. Deputppy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deoria, PO- Tadong, Gangtok	737102
24	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjanban, Agartala	799006
26	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojni Naidu, Marg, Allahabad	211001
27	Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Lucknow, Audit Bhawan, 4th Floor, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh	226010
28	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majram, Dehradun	248171
29	Pr. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, No.-2, Govt. Place (West), Kolkata	700001
30	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry	605001
31	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
32	Pay & Accounts Officer(V), Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi	110124
33	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject: Grant of Dearness Relief/ Medical Allowance/ Revision of pension/ amendment of pension rules of state government pensioner.

Reference: Government resolution No-

(1) ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता-01/2024-2140/वि0 पटना, दिनांक-28.02.2024

(2) ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता-01/2022-2892/वि0 पटना, दिनांक-15.03.2024

(3) ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता-01/2022-2893/वि0 पटना, दिनांक-15.03.2024

(4) ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता-01/2022-2894/वि0 पटना, दिनांक-15.03.2024

Sir,

I am to forward herewith Hindi/ English version of copy of Govt. of Bihar resolution mentioned above for your needful action. You are requested to circulate this order to all concern pensions disbursing authority under your jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same.

Enclosure: Resolution of Government of Bihar.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

पत्रांक–3ए–3–भत्ता–01 / 2024– 2140 / वि०, पटना, दिनांक:– 28/02/2024

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषयः– **बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा के उपरान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–04.01.2024 के आलोक में विभिन्न भत्ता/ सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में।**

वित्त विभागीय संकल्प संख्या–9154, दिनांक–28 / 09 / 2022 एवं संकल्प संख्या–6649, दिनांक–28 / 07 / 2023 द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन एवं पेंशनादि लाभ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल ऑरिजनल/ इन्हेरेंट/एक्स्ट्रा–ऑर्डिनरी अपीलेट जूरिस्डीक्शन, रिट पिटीशन (सिविल) संख्या– 643 / 2015 (ऑल इंडिया जजेज एशोसियेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में दिनांक–04 / 01 / 2024 को पारित आदेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को भत्ता एव सुविधाओं के पुनरीक्षण का विषय, राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. सम्यक् विचारोपरांत बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निम्नलिखित भत्तों की स्वीकृती प्रदान की जाती है :–

[I.] गृह निर्माण अग्रिम :–

(a) गृह निर्माण अग्रिम आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत HBA Rules, 2017 के अनुरूप अनुमान्य होगा।

(b) निजी व्यक्तियों से बने बनाये मकान खरीदने हेतु आवश्यक प्रावधान, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्गत किया जाएगा।

[II.] शिशु शिक्षा भत्ता :–

(a) बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के प्रभाव से शिशु शिक्षा भत्ता प्रतिमाह ₹2,250/- एवं छात्रावास अनुदान ₹6,750/- प्रतिमाह अथवा वास्तविक खर्च, जो कम हो, की दर से अधिकतम दो संतानों हेतु बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए अनुमान्य किया जायेगा।

(b) दिव्यांग बच्चों के लिए उपरि कडिका में वर्णित दर के दोगुने दर से भुगतान/प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगा।

(c) महंगाई भत्ता 50% होने पर उपरोक्त भत्ता एवं अनुदान में 25% की बढ़ोत्तरी की जाएगी।

(d) शिशु शिक्षा भत्ता एवं छात्रावास अनुदान की प्रतिपूर्ति संस्थान के प्रधान द्वारा व्यय को अंकित करते हुए निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर की जाएगी।

[III.] नगर क्षतिपूरक भत्ता:–

नगर क्षतिपूरक भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। पूर्व में यदि उक्त मद में भुगतान हुआ हो, तो उसकी वसूली नहीं की जायेगी।

[IV.] अतिरिक्त प्रभार के लिए भत्ता (Concurrent Charge):–

(a) यह भत्ता, 10 कार्य दिवस से अधिक के अतिरिक्त प्रभार वाले पद के वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम का 10% होगा।

(b) उक्त सीमा के अधीन कार्य दिवस में किए गए न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पदाधिकारियों को मिलने वाले अतिरिक्त प्रभार के लिए (Concurrent Charge) भत्ता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

[V.] वाहन/परिवहन भत्ता :–

(a) पुल कार व्यवस्था समाप्त की जाती है। परन्तु, ऐसी सुविधा प्राप्त न्यायिक पदाधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए पुल कार सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें परिवहन भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(b) बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, जो अपने निजी वाहन का उपयोग सरकारी कार्य हेतु करते हों, उन्हें रख–रखाव एवं चालक हेतु रु० 10,000/- प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ता दिनांक–01/01/2016 के प्रभाव से अनुमान्य होगा। दिनांक–01/01/2021 के प्रभाव से यह दर रु० 13,500/- हो जायेगा। जिन पदाधिकारियों के पास अपना निजी वाहन नहीं है और वे पुल कार की सुविधा भी प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें भी उक्त दर से परिवहन भत्ता अनुमान्य होगा। पुनः जिन पदाधिकारियों को वाहन चालक के रूप में कार्यालय परिचारी उपलब्ध कराया गया है, उन्हें दिनांक–01/01/2016 के प्रभाव से रु० 4,000/- प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ता अनुमान्य होगा। दिनांक–01/01/2021 से यह राशि रु० 5000/- प्रतिमाह होगी। ईंधन भत्ता के अतिरिक्त यह लाभ देय होगा।

(c) न्यायिक पदाधिकारी, जो अपने निजी वाहन का उपयोग सरकारी कार्य हेतु करते हों, को शहरी क्षेत्र हेतु 100 लीटर पेट्रोल/डीजल एवं अन्य क्षेत्रों हेतु 75 लीटर पेट्रोल/डीजल प्रतिमाह अनुमान्य हो सकेगा। यह प्रतिपूर्त्ति वास्तविक खपत के आलोक में स्व–प्रमाणन (Self-Certification) के आधार पर की जाएगी।

(d) पूर्व से सरकारी वाहन की सुविधा प्राप्त कर रहे न्यायिक पदाधिकारियों की सूची में निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी अथवा न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार भी शामिल होंगे।

(e) सरकारी कार्य हेतु सरकारी वाहन से की गई यात्रा हेतु ईंधन की अधिसीमा वास्तविक खपत के हद तक लॉग बुक एवं संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणन के आधार पर अनुमान्य होगा। निजी उद्देश्यों के लिए सरकारी वाहन का उपयोग 300 किलोमीटर (प्रतिमाह) की अधिसीमा तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किया जा सकेगा। सरकारी वाहन के निजी उपयोग की गणना अर्द्ध–वार्षिक आधार पर की जाएगी।

(f) न्यायिक पदाधिकारी अपने वाहन के बायीं ओर मध्यम आकार के "जज" नामक स्टीकर का प्रयोग कर सकेंगे, जिसके सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक मार्ग–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

(g) न्यायिक पदाधिकारियों को 10 लाख रूपये की अधिसीमा तक सुलभ ब्याज दर पर मोटरकार खरीदने हेतु ऋण सुविधा (soft loan) उपलब्ध कराया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत प्रावधान/प्रक्रिया वित्त विभाग द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से निर्धारित किया जायेगा।

[VI.] महँगाई भत्ता :–

बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत दर के अनुसार महँगाई भत्ता अनुमान्य होगा।

[VII.] उपार्जित अवकाश नकदीकरण :–

न्यायिक पदाधिकारियों को उपार्जित अवकाश का नकदीकरण निम्न रूप से अनुमान्य होगा:–

(a) L.T.C. का उपभोग करने के क्रम में, 10 दिनों के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण, सम्पूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम छः बार, कुल 60 दिनों के लिए अनुमान्य होगा।

(b) दो वर्षों के ब्लॉक में 30 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमान्य होगा।

(c) उपर्युक्त (a) एवं (b) के अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति के समय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश का नकदीकरण 300 दिनों के अधिसीमा तक अनुमान्य होगा।

(d) दिनांक–01/01/2016 के उपरांत सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, जिन्हें उपरोक्त कंडिका–(a) एवं (b) के अधीन अनुमान्य छुट्टी के नकदीकरण को सेवानिवृत्ति के समय छुट्टी नकदीकरण के विरुद्ध समायोजित किया गया हो तो उक्त समायोजित अवधि का भुगतान संकल्प निर्गत होने के तीन माह के अंदर किया जाएगा।

[VIII.] विद्युत एवं जल शुल्क :–

(a) राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा उनके आवास के लिए विद्युत एवं जल शुल्क के रूप में किये गये मासिक भुगतान का 50% की राशि की प्रतिपूर्ति, वास्तविक अभिश्रव के विरुद्ध की जायेगी।

(b) जल एवं विद्युत के उपभोग की अधिसीमा निम्नवत् होगी:–

पदनाम	विद्युत यूनिट (Unit)	जल की मात्रा
जिला जज	8000 units प्रतिवर्ष	420 Kls प्रतिवर्ष
सिविल जज	6000 units प्रतिवर्ष	336 Kls प्रतिवर्ष

उपर्युक्त संशोधित दर दिनांक– 01/01/2020 से प्रभावी होगी।

[IX.] उच्चतर शिक्षा भत्ता :–

न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विधि में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने पर तीन अग्रिम वेतन–वृद्धि एवं पीएच०डी० की उपाधि प्राप्त करने पर एक अतिरिक्त अग्रिम वेतन–वृद्धि का लाभ अनुमान्य होगा। नियुक्ति के पूर्व उपरोक्त उपाधि धारित करने की स्थिति में यह लाभ नियुक्ति की तिथि से तथा सेवा अवधि में उपरोक्त उपाधि प्राप्त करने पर, उपाधि प्राप्ति की तिथि से अनुमान्य होगा। एक बार अग्रिम वेतन–वृद्धि प्राप्त करने के बाद किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट डिग्री के लिए अग्रिम वेतन–वृद्धि अनुमान्य नहीं होगा। अग्रिम वेतन–वृद्धि नियमित एवं डिस्टेन्स लर्निंग प्रोग्राम से प्राप्त डिग्री, दोनों मामलों में प्राप्त होगा।

[X.] होम अर्दली / घरेलू सहायता भत्ता :–

बिहार न्यायिक सेवा के कार्यरत पदाधिकारियों को दिनांक–01/01/2016 के प्रभाव से निम्न दर से घरेलू–सह–कार्यालय सहायता भत्ता अनुमान्य होगा :–

(a) **जिला जज**– राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक जो, रु० 10,000/- प्रतिमाह से कम न हो।

(b) **सिविल जज–** राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक का 60%, जो रु० 7,500/- प्रतिमाह से कम न हो।
घरेलू कार्य के लिए जिन्हें परिचारी की सेवा उपलब्ध है, उन्हें उपरोक्त भत्ता अथवा परिचारी की सेवा, में से एक का विकल्प देना होगा।

(c) बिहार न्यायिक सेवा के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनरों को क्रमशः रु० 9,000/- प्रतिमाह एवं रु० 7,500/- प्रतिमाह की दर से दिनांक–01/01/2016 के प्रभाव से घरेलू सहायता भत्ता अनुमान्य हो सकेगा। यह भत्ता दिनांक– 01/01/2021 के प्रभाव से 30% के वर्द्धित दर से अनुमान्य होगा।

(d) यह भत्ता स्व–प्रमाणन के आधार पर भुगतेय होगा।

[XI.] मकान किराया भत्ता :–

(a) जिन न्यायिक सेवा के अधिकारियों को सरकारी आवास आवंटित है, वे मकान किराया भत्ता के हकदार नहीं होंगे।

(b) माता–पिता/पति–पत्नी या स्वयं के घर में रहने वाले न्यायिक पदाधिकारी हेतु अनुशंसित मकान किराया भत्ता, दिनांक–01/01/2016 के प्रभाव से अनुमान्य होगा। इसके लिए उन्हें उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी। वैसे पदाधिकारी, जो पूर्व से ही किराये के मकान में रहते हैं, उन्हें दिनांक–01/01/2020 के प्रभाव से वास्तविक किराया की प्रतिपूर्ति निर्धारित अधिसीमा के अन्दर प्राप्त होगा।

(c) वैसे न्यायिक पदाधिकारी, जो किराये के मकान में स्व–प्रयास से रहते हैं, के मकान किराये (HRA की निर्धारित अधिसीमा तक) का भुगतान संबंधित प्रधान न्यायाधीश एवं समकक्ष द्वारा सीधे मकान मालिक को किया जायेगा। ऐसे मामलों में सबंधित न्यायिक पदाधिकारी को मकान किराया भत्ता की प्रतिपूर्ति अनुमान्य नहीं होगी।

(d) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मकान किराया भत्ता, O.M. No. 20/5/17-E दिनांक–07/07/2017 न्यायिक पदाधिकारियों के मामले में लागू होगा।
मकान किराया भत्ता निम्न दर से शहरों के वर्गीकरण के आधार पर अनुमान्य होगा:–

शहरों के वर्गीकरण	मकान किराया भत्ता की मासिक दर (मूल वेतन के % के रूप में)
X	24%
Y	16%
Z	8%

उपरोक्त वर्गीकरण के आलोक में मकान किराया भत्ता का निर्धारित दर के अनुसार, क्रमशः न्यूनतम 5400/-, 3600/- एवं 1800/- से कम नहीं होगा।

(c) महँगाई भत्ता में परिवर्तन होने पर मकान किराया भत्ता निम्न रूप से अनुमान्य होगा:–

शहरों का वर्गीकरण	महँगाई भत्ता 25% होने पर मकान किराया भत्ता का दर	महँगाई भत्ता 50% होने पर मकान किराया भत्ता का दर
X	27%	30%
Y	18%	20%
Z	9%	10%

(f) **फर्नीचर एवं एयरकंडिशनर भत्ता :–**

(a) न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को प्रत्येक पाँच वर्ष पर रु० 1.25 लाख का फर्नीचर अनुदान वास्तविक अभिश्रव प्रस्तुत करने पर अनुमान्य होगा। जिन पदाधिकारियों की सेवानिवृति हेतु सेवा–अवधि दो वर्ष से कम न हो, वे भी इस अनुदान के पात्र होंगे। उक्त अनुदान से घरेलू विद्युत उपकरण भी खरीदे जा सकते हैं। अधिकारी द्वारा उपयोग किये जा रहे फर्नीचर को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य ह्रास दर पर खरीदने का विकल्प नये अनुदान या सेवानिवृत्ति के समय उपलब्ध होगा।

(b) फर्नीचर अनुदान के अलावा, प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के आवास पर हर पाँच साल में एक बार एयरकंडीशनर (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिसीमा तक) वास्तविक अभिश्रव के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

(c) मकान किराया भत्ता एवं निजी आवास/क्वार्टर/अतिथि गृह–सह–ट्रांजिट होम के संबंध में विस्तृत आदेश अलग से वित्त विभाग द्वारा सम्बन्धित विभाग के परामर्श से निर्गत किया जाएगा।

[XII.] एल०टी०सी० / एच०टी०सी० :–

(a) न्यायिक अधिकारियों को 03 वर्षों के ब्लॉक में एक LTC एवं एक HTC की अनुमति दी जा सकेगी। नव–नियुक्त न्यायिक पदाधिकारियों को प्रथम तीन वर्षों के ब्लॉक में दो HTC अनुमान्य होगा। ब्लॉक वर्ष की गणना परिवीक्षा अवधि के समाप्ति के उपरांत की जायेगी।

(b) सभी कोटि के न्यायिक पदाधिकारी को LTC हेतु हवाई यात्रा अनुमान्य होगी। इस हेतु टिकट की खरीदगी सरकार द्वारा निर्धारित एजेन्सी अथवा सीधे वायुयान कम्पनी से की जानी होगी तथा यात्रा की श्रेणी/अग्रिम आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अनुमान्य होंगी।

(c) न्यायिक पदाधिकारी बकाये LTC का उपयोग सेवानिवृत्ति के उपरान्त एक वर्ष की सीमा के अन्तर्गत करेंगे।

(d) LTC स्वीकृत करते समय 10 दिनों की अर्जित छुट्टी का नकदीकरण (अधिकतम 60 दिनों के अधीन) अनुमान्य होगा। यह सेवानिवृत्ति के समय 300 दिन और दो वर्ष के ब्लॉक में 30 दिनों के नकदीकरण के अतिरिक्त होगा। इस सुविधा का उपभोग करते समय उपार्जित अवकाश के प्रारम्भ एवं अन्त में से एक अवसर पर दो आकस्मिक अवकाश जोड़ा जा सकेगा।

(e) इस संबंध में आवश्यक विस्तृत आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

[XIII.] चिकित्सा भत्ता :–

दिनांक–01/01/2016 के प्रभाव से कार्यरत न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रतिमाह रु० 3000/- की दर से एवं सेवानिवृत्त पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को प्रतिमाह रु० 4000/- की दर से चिकित्सा भत्ता अनुमान्य होगा।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में आवश्यक प्रावधान किये जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग से सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

[XIV.] समाचार पत्र एवं पत्रिका भत्ता :–

(a) जिला न्यायाधीश को प्रतिमाह दो समाचार पत्र एवं दो पत्रिका के लिए क्रमशः रु० 1000/- एवं सिविल जज के लिए दो समाचार पत्र तथा एक पत्रिका हेतु रु० 700/- की प्रतिपूर्त्ति की जाएगी।

(b) यह प्रतिपूर्त्ति अर्द्ध–वार्षिक आधार पर जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसम्बर के लिए स्व–प्रमाणन (Self-Certification) के आधार पर अनुमान्य होगा।

(c) यह दर दिनांक–01/01/2020 से प्रभावी होगा।

[XV.] पोशाक भत्ता :–

(a) प्रत्येक तीन वर्ष पर पोशाक भत्ता के रूप में रु० 12,000/- का नगद भुगतान किया जायेगा, जो दिनांक–01/01/2016 से प्रभावी होगा।

[XVI.] प्रशासनिक कार्यों के लिए विशेष वेतन :–

(a) प्रशासनिक कार्य करने वाले निम्नलिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके पदनाम के सामने अंकित दर से विशेष वेतन अनुमान्य होगा :–

पदनाम	अनुमान्य विशेष वेतन
प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश	7000/– प्रतिमाह।
न्यायालीय कार्यों के अतिरिक्त प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश, जो विशेष न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष हों।	3500/– प्रतिमाह।

सी०जे०एम० और प्रधान वरिष्ठ, कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अन्य पदाधिकारी, (जिनके पास स्वतंत्र न्यायालयों के प्रभारी होने के नाते फाइलिंग शक्तियों के साथ प्रशासनिक जिम्मेवारियाँ हों)।	2000/- प्रतिमाह

उपरोक्त सभी विशेष वेतन दिनांक–01/01/2019 से प्रभावी होगा।

[XVII.] आतिथ्य भत्ता :–

(a) दिनांक–01/01/2016 के प्रभाव से निम्न दर से आतिथ्य भत्ता अनुमान्य होगा:–

जिला जज	–	7800/- प्रतिमाह
सिविल जज (सिनियर डिविजन)	–	5800/- प्रतिमाह
सिविल जज (जूनियर डिविजन)	–	3800/- प्रतिमाह

(b) प्रधान जिला न्यायाधीश (जो प्रशासनिक कार्यों के प्रभार में हों) / जिला न्यायाधीश (प्रवर कोटि अथवा अधिकाल वेतनमान)/निदेशक, न्यायिक अकादमी/न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान/सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, को **रु० 1000/- प्रतिमाह** के दर से अतिरिक्त आतिथ्य भत्ता अनुमान्य होगा।

(c) सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को आतिथ्य भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

[XVIII.] दूरभाष/मोबाईल भत्ता :–

(a) न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को दूरभाष सुविधा निम्न प्रकार से देय होगा:–

(i) **आवासीय दूरभाष (लैंडलाईन फोन) ब्रॉडबैण्ड सुविधा सहित :**

जिला जज	–	1500/- प्रतिमाह
सिविल जज	–	1000/- प्रतिमाह

(ii) **वैसे स्थान जहाँ पर ब्रॉडबैण्ड सुविधा उपलब्ध नहीं हो :**

जिला जज	–	1000/- प्रतिमाह
सिविल जज	–	750/- प्रतिमाह

(iii) **मोबाईल फोन** : न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को मोबाईल फोन निम्न दर से देय होगी:–

पदनाम	–	**हैण्डसेट मूल्य**	–	**कॉल एवं डाटा पैक**
जिला जज	–	30,000/-	–	2000/- प्रतिमाह
सिविल जज (सिनियर एवं जूनियर डिविजन)	–	20,000/-	–	1500/- प्रतिमाह

(b) न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के अनुरोध पर मोबाईल फोन हैण्डसेट को 03 वर्ष पर एक बार बदला जा सकेगा। अधिकारी द्वारा उपयोग किये जा रहे पुराने मोबाईल को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य ह्रास दर पर खरीदने का विकल्प दिया जायेगा। इस हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

(c) कार्यालय दूरभाष की सुविधा पूर्ववत् रहेगा।

[XIX.] स्थानांतरण अनुदान :–

(a) राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने पर एक माह के मूल वेतन के बराबर राशि का एक मुश्त भुगतान स्थानांतरण अनुदान के रूप में दिया जायेगा, परन्तु 20 किलोमीटर या इससे कम दूरी अथवा समान शहर, जिसमें निवास स्थान वास्तव में परिवर्तित हो रहा हो, की दशा में मूल वेतन का एक–तिहाई राशि एक मुश्त स्थानांतरण अनुदान के रूप में दी जायेगी।

(b) घरेलू समान की ढुलाई हेतु, भारत सरकार के व्यय विभाग द्वारा दिनांक–13/07/2017 को निर्गत O.M. के प्रावधान लागू होंगे। सड़क मार्ग से परिवहन के मामले में अनुमान्य राशि रु० 50/- प्रति किलोमीटर होगी (जिसमें लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए श्रम शुल्क शामिल है) या वास्तविक जो भी कम हो, अनुमान्य होगा। महँगाई भत्ता 50% होने पर उक्त दर में 25% वृद्धि होगी।

(c) उपरोक्त भत्ता दिनांक–01/01/2016 के प्रभाव से लागू होगा। वैसे न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, जो दिनांक–01/01/2016 के बाद स्थानांतरित हुये हों, उन्हें पुनरीक्षित दर के अनुसार अन्तर राशि देय होगी।

4. जिन भत्तों के भुगतान में अभिश्रव की आवश्यकता है, उन भत्तों का भुगतान भी संकल्प निर्गत होने के माह तक स्व–प्रमाणन (Self-Certification) के आधार पर अनुमान्य होगा, परन्तु संकल्प निर्गत होने के माह के पश्चात् के लिए भुगतान यथानिर्धारित विधि से अनुमान्य होगा।

5. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत संकल्प के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का वित्त विभाग द्वारा निराकरण किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक–3ए–3–भत्ता–01/2024-_____/वि० पटना, दिनांक-_____

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक–3ए–3–भत्ता–01/2024-_____/वि० पटना, दिनांक-_____

प्रतिलिपि– महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक–3ए–3–भत्ता–01/2024-_____/वि० पटना, दिनांक-_____

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग /अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा / सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) / प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक–3ए–3–भत्ता–01/2024-2140/वि० पटना, दिनांक-28/02/2024

प्रतिलिपि– सरकार के विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–27.02.2024 के मद संख्या–02 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।
28/02/2024

Letter No. 3A-3-Allowance-01/2024-2140/Vi. Patna, dated 28/02/2024

GOVERNMENT OF BIHAR

DEPARTMENT OF FINANCE

RESOLUTION

Sub:- Sanction of various allowances/facilities to Bihar Judicial Service Officers, in the light of Order dated 04.01.2024 passed by the Honourable Supreme Court, New Delhi after the recommendation of the Second National Judicial Pay Commission – reg.

Vide Department of Finance Resolution No. 9154 dated 28/09/2022 and Resolution No. 6649, dated 28/07/2023, the benefits of revised pay and pension etc. have been sanctioned to Bihar Judicial Service Officers.

2. In the light of the order passed by the Honourable Supreme Court, New Delhi on 04/01/2024, in Civil Original / Inherent / Extra Ordinary Appellate Jurisdiction, Writ Petition (Civil) No. 643/2015 (All India Judges Association Vs Union of India and Others), the matter of revision of allowances and facilities to Bihar Judicial Service Officers was under consideration of the State Government.

3. After due consideration, the following allowances are sanctioned to Bihar Judicial Service Officers:

[I.] HOUSE BUILDING ADVANCE:-

(a) House Building Advance shall be permissible in terms of HBA Rules, 2017 issued by the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.

(b) Necessary provisions for the purchase of a ready built house from private individuals will be issued by the State Government, in consultation with the High Court.

[II.] CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE:-

(a) The Bihar Judicial Service Officers shall be permitted ₹2,250/- per month as Children Education Allowance and ₹6,750/- per month as hostel subsidy or actual expenses, whichever is less, for the education of maximum two children up to class 12, with effect from the academic year 2019-20.

(b) For children with special needs, payment/reimbursement will be permissible at double the rate stated in the above paragraph.

(c) When the Dearness Allowance becomes 50%, the above allowance and subsidy shall increase by 25%.

(d) Reimbursement of Children Education Allowance and Hostel Subsidy shall be done on the basis of a certificate issued by the head of the institute, mentioning the expenditure.

[III.] CITY COMPENSATORY ALLOWANCE:-

City Compensatory Allowance shall not be permissible. No recovery shall be effected on the amount already paid on account of the above item.

[IV.] CONCURRENT CHARGES ALLOWANCE:-

(a) This allowance will be 10% of the minimum stage of the pay scale of the additional post held beyond a period of 10 working days.

(b) The Honourable High Court will decide the Concurrent Charges allowance available to the Judicial Officers on the basis of the judicial and administrative work done within the above ceiling of working days.

[V.] CONVEYANCE/TRANSPORT ALLOWANCE :-

(a) The pool car system is abolished. However, the judicial officers having such facility can avail the pool car facility for a period of one year. In such a situation, transport allowance will not be permissible to them.

(b) The transport allowance at the rate of Rs.10,000/- per month with effect from 01/01/2016 shall be permissible to those Bihar Judicial Service Officers who use their private vehicles for official purposes, so as to cover the cost of maintenance and driver. This rate will be increased to Rs.13,500/- with effect from 01/01/2021. Those officers who do not have their own personal vehicle and do not avail the pool car facility will also be permitted transport allowance at the above rate. Further, the transport allowance at the rate of Rs.4,000/- per month will be permitted with effect from 01/01/2016 to those officers who have been provided with an Office Attendant as driver. This amount will be increased to Rs.5000/- per month from 01/01/2021. This benefit will be payable in addition to fuel allowance.

(c) Judicial Officers, who use their private vehicles for official purposes, will be allowed 100 litres of petrol/diesel per month for urban areas and 75 litres of petrol/diesel per month for other areas. This reimbursement will be done on the basis of Self-Certification, in the light of actual consumption.

(d) The list of Judicial Officers already availing the facility of Government vehicle will also include the Director, Bihar Judicial Academy or Judicial Training Institute/Principal Judge, Family Court/Secretary, District Legal Services Authority.

(e) The ceiling of fuel for travel done by official vehicle for official purposes shall be allowed to the extent of actual consumption on the basis of logbook and certification by the concerned officer. Government vehicles can be used for private purposes up to the ceiling of 300 kilometres (per month) at the rate prescribed by the State Government. Private use of government vehicle will be calculated on half-yearly basis.

(f) The Judicial Officers shall be permitted to exhibit a sticker on the left side of their vehicle with inscription "Judge" printed in moderately sized letters, regarding which necessary guidelines will be issued by the Transport Department.

(g) Soft loan facility to the extent of Rs.10 lakhs at nominal interest rate for the purchase of motor car shall be extended to Judicial Officers. Detailed provisions/ procedure in this regard shall be prescribed by the Department of Finance, in consultation with the High Court.

[VI.] DEARNESS ALLOWANCE:-

Dearness allowance will be permissible to Bihar Judicial Service Officers as per the rate sanctioned by the Central Government, from time to time.

[VII.] EARNED LEAVE ENCASHMENT :-

Encashment of earned leave to Judicial Officers will be permissible as follows:-

(a) Encashment of 10 days earned leave while availing LTC, subject to maximum 60 days up to six occasions during the entire career will be permissible.

(b) Encashment of 30 days earned leave in a block of two years will be permissible.

(c) In addition to (a) and (b) above, encashment of earned leave up to 300 days will be permissible at the time of retirement.

(d) The Judicial Officers, who have retired after 01/01/2016 and whose encashment of leave permitted under para (a) and (b) above stands adjusted against the leave encashment at the time of retirement, shall be paid for the adjusted period within three months of issue of the Resolution.

[VIII.] ELECTRICITY AND WATER CHARGES: -

(a) 50% of the amount of monthly payment made by the State Judicial Service Officers as electricity and water charges for their residence shall be reimbursed against the actual voucher of payment.

(b) The ceiling for consumption of water and electricity shall be as follows:-

Designation	Electricity Units	Quantity of Water
District Judges	8000 units per annum	420 Kls per annum
Civil Judges	6000 units per annum	336 Kls per annum

The above revised rates will be effective from 01/01/2020.

[IX.] HIGHER QUALIFICATION ALLOWANCE:-

The Judicial Service Officers shall be permitted the benefit of three advance increments for acquiring post-graduation in Law and one additional advance increment on acquiring Ph.D. in Law. This benefit will be permissible from the date of appointment if the degree has been acquired before appointment and from the date of acquiring the degree if acquired during the service period. The advance increment once received shall not be permissible for acquiring postgraduate or doctorate degree in any other subject. The advance increment shall be granted for acquiring degree through both regular and distance learning programmes.

[X.] HOME ORDERLY/DOMESTIC HELP ALLOWANCE: -

The Home-cum-office orderly allowance shall be permissible to the serving Bihar Judicial Service Officers at the following rate, with effect from 01/01/2016:

(a) **District Judges** – Minimum monthly wages fixed by the State Government for one unskilled worker, subject to minimum of Rs.10,000/- per month.

(b) **Civil Judges** – 60% of the minimum monthly wages fixed by the State Government for one unskilled worker, subject to minimum of Rs.7,500/- per month.

Those provided with the services of an Attendant for domestic work will have to opt either for the above allowance or the services of the Attendant.

(c) Domestic Help Allowance to the pensioners and family pensioners of Bihar Judicial Services shall be permissible at the rate of Rs.9,000/- per month and Rs.7,500/- per month respectively, with effect from 01/01/2016. This allowance increased by 30% shall be permissible with effect from 01/01/2021.

(d) This allowance will be payable on the basis of self-certification.

[XI.] HOUSE RENT ALLOWANCE:-

(a) Judicial Service Officers who are allotted official quarters for residence shall not be entitled to House Rent Allowance.

(b) Judicial officers residing in their own houses including the house of a parent or spouse, shall be permitted the recommended House Rent Allowance with effect from 01/01/2016. For this they have to obtain permission from the High Court. Those officers, already residing in hired accommodation will receive reimbursement of actual rent paid within the prescribed ceiling with effect from 01/01/2020.

(c) In case of those Judicial Officers who are voluntarily residing in hired accommodation, the concerned Principal Judge or equivalent shall pay the house rent (up to the prescribed ceiling of HRA) directly to the landlord. In such cases, reimbursement of House Rent Allowance will not be permissible to the concerned Judicial Officer.

(d) The House Rent Allowance notified by the Central Government as per O.M. No. 20/5/17- E dated 07/07/2017 shall be applicable to all Judicial Officers.

House Rent Allowance will be permissible at the following rates based on the classification of cities: -

Classification of Cities	Rates of HRA/pm (as % of basic pay)
X	24%
Y	16%
Z	8%

In the light of the above classification, the minimum rates of House Rent Allowance prescribed are Rs.5400/-, Rs.3600/- and Rs.1800/- respectively.

(e) In accordance with the change in Dearness Allowance, the House Rent Allowance will be permissible in the following terms: -

Classification of cities	Rates of HRA when Dearness Allowance is 25%	Rates of HRA, when Dearness Allowance is 50%
X	27%	30%
Y	18%	20%
Z	9%	10%

(f) **FURNITURE AND AIR CONDITIONER ALLOWANCE: -**

(a) Furniture grant of Rs 1.25 lakhs every five years shall be permissible to the Judicial Service Officers subject to production of actual vouchers of expenditure. The officers having not less than two years of service for retirement will also be eligible for this grant. Household electrical appliances can also be purchased by availing the said grant. The option to purchase the furniture being used by the officer at the depreciated rate prescribed by the State Government shall be available at the time of fresh grant or retirement.

(b) Apart from the furniture grant, AirC (up to the limit prescribed by the State Government) shall be provided at the residence of every Judicial Officer once in every five years on the basis of original vouchers.

(c) Detailed orders regarding House Rent Allowance and private accommodation/quarter/guest house-cum-transit home will be issued separately by the Department of Finance, in consultation with the concerned department.

[XII.] L.T.C. / H.T.C. :-

(a) The Judicial officers may be permitted to avail one LTC and one HTC in a block of 03 years. The newly recruited Judicial Officers shall be allowed HTC for 2 times in the first block of three years. The block year will be calculated after completion of the period of probation.

(b) The Judicial Officers irrespective of their rank shall be allowed to travel by air for LTC. For this, tickets should be purchased either from the agency prescribed by the Government or directly from the Airline company and the class of travel/advance etc. will be permissible subject to the conditions prescribed by the State Government.

(c) The Judicial Officers shall utilise the outstanding LTC beyond retirement for a period of one year.

(d) Encashment of 10 days earned leave (subject to the maximum of 60 days) will be permissible while sanctioning LTC. The same will be in addition to the encashment of 300 days at the time of retirement and 30 days in a block of two years. While availing this facility, they may be permitted to avail casual leave as a prefix and suffix with the earned leave to the extent of 2 days.

(e) Necessary detailed orders in this regard will be issued separately.

[XIII.] MEDICAL ALLOWANCE: -

Medical Allowance will be permissible at the rate of Rs. 3000/- per month to the serving Judicial Service Officers and Rs.4000/- per month to the retired pensioners/family pensioners, with effect from 01/01/2016.

To make necessary provisions regarding medical reimbursement, sanction of competent authority will be obtained separately by the Health Department.

[XIV.] NEWSPAPER AND MAGAZINE ALLOWANCE: -

(a) Reimbursement of Rs.1000/- per month will be made to the District Judge for two newspapers and two magazines and Rs.700/- per month to the Civil Judge for two newspapers and one magazine.

(b) This reimbursement shall be permissible on half-yearly basis from January to June and July to December, on the basis of self-certification.

(c) The above rate will be effective from 01/01/2020.

[XV.] ROBE ALLOWANCE:-

(a) Payment of Robe Allowance of Rs 12,000/- will be made in cash once in three years, with effect from 01/01/2016.

[XVI.] SPECIAL PAY FOR ADMINISTRATIVE WORK:-

(a) Special pay will be permissible to the following Judicial Officers doing administrative work at the rate mentioned against their designation: -

Designation	Permissible Special Pay
Principal and District Sessions Judges	7000/- per month
District Judges/Additional District Judges/ District Judges presiding over Special Courts and Tribunals, discharging administrative duties in addition to judicial functions.	3500/- per month.

CJMs and Principal Senior, Junior Civil Judges and other Officers (having administrative responsibilities being in charge of independent Courts with filing powers).	2000/- per month

All the above special pay will be effective from 01/01/2019.

[XVII.] SUMPTUARY ALLOWANCE:-

(a) Sumptuary allowance will be permissible with effect from 01/01/2016 at the following rate: -

District Judges	-	7800/- per month
Civil Judges (Senior Division)	-	5800/- per month
Civil Judges (Junior Division)	-	3800/- per month

(b) Additional Sumptuary Allowance at the rate of **Rs.1000/- per month** shall be permissible to the Principal District Judge (in charge of administrative functions) / District Judge (selection grade or super time-scale) / Director, Judicial Academy / Judicial Training Institute / Member Secretary, State Legal Services Authority and Chief Judicial Magistrate.

(c) No Sumptuary Allowance shall be permissible to retired Judicial Officers.

[XVIII.] TELEPHONE/MOBILE ALLOWANCE: -

(a) The Judicial Service Officers shall be provided with the following telephone facilities: -

i. Residential Telephone (Landline Phone) with broadband facility

District Judges	-	1500/- per month
Civil Judges	-	1000/- per month

ii. Places where broadband facility is not available:

District Judges	-	1000/- per month
Civil Judges	-	750/- per month

iii. Mobile Phone: The Judicial Service Officers shall be provided with Mobile Phone at the following rates: -

Designation	**Cost of Handset**	**Call & Data Pack**
District Judges	30,000/-	2000/- per month
Civil Judges (Senior and Junior Division)	20,000/-	1500/- per month

(b) At the request of Judicial Service Officers, the mobile phone handset shall be replaced once in 03 years. Option shall be given to purchase the old mobile phone being used by the officer at the depreciated rate as prescribed by the State Government. Guidelines will be issued in this regard.

(c) Office telephone facility will remain the same.

[XIX.] TRANSFER GRANT :-

(a) On transfer of State Judicial Service Officers, lump sum payment of the amount equivalent to one month's basic pay will be made as transfer grant, but if the transfer is to a place at a distance of 20 kilometres or less or within the same city which involves actual change of residence, one-third of the basic pay will be given as lump sum transfer grant.

(b) For transportation of household goods, the provisions of O.M. issued on 13/07/2017 by the Department of Expenditure, Government of India will be applicable. In case of transportation by road, the permissible amount shall be Rs. 50/- per kilometre (inclusive of labour charges for loading and unloading) or actual, whichever is lower. The said rate shall be raised by 25%, when the dearness allowance beocmes 50%.

(c) The above allowance will be applicable with effect from 01/01/2016. Those Judicial Service Officers who have undergone transfer(s) after 01/01/2016 shall be paid the differential amount as per the revised rate.

4. Payment of those allowances which requires vouchers of expenditure shall also be permissible on the basis of self-certification till the month of issue of Resolution, but payment after the month of issue of Resolution will be permissible as per the prescribed procedure.

5. The difficulties faced in the impiementation of the Resolution issued in compliance with the orders passed by the Honourable Supreme Court, New Delhi in the light of the recommendations of the Second National Judicial Pay Commission, to Bihar Judicial Service Officers, shall be resolved by the Department of Finance.

By orders of the Governor of Bihar

Sd/-

(Lokesh Kumar Singh)

Secretary (Resources), Department of Finance

Memo No. 3A-3- Allowance-01/2024..... / Vi. Patna, Dated.....

Copy to - Office of the Accountant General (A&E), Veerchand Patel Path, Patna, Bihar, sent for information and necessary action.

Sd/-
(Lokesh Kumar Singh)
Secretary (Resources), Department of Finance

Memo No. 3A-3- Allowance-01/2024..... / Vi. Patna, Dated.....

Copy to – The Registrar General, High Court, Patna / Secretary, Bihar Legislative Assembly / Secretary, Bihar Legislative Council, Bihar, Patna, sent for information and necessary action.

Sd/-
(Lokesh Kumar Singh)
Secretary (Resources), Department of Finance

Memo No. 3A-3- Allowance-01/2024..... / Vi. Patna, Dated.....

Copy to - All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries / All Secretaries / All Divisional Commissioners / All District Officers / All Treasury Officers / All District Accounts Officers / Officers in Charge , Finance (PCFC) Department / Under Secretary, Pay Fixation Branch / System Analyst (for uploading on the website of Department of Finance) / Officer-in-Charge, E-Gazette Branch, Department of Finance, Bihar, Patna, sent for information and necessary action.

Sd/-
(Lokesh Kumar Singh)
Secretary (Resources), Department of Finance

Memo No. 3A-3- Allowance-01/2024- 2140 / Vi. Patna, Dated 28.02.2024

Copy to - The Special Secretary to Government, Department of Cabinet Secretariat, Bihar, Patna, in the light of Item No. 02 of meeting dated 27.02.2024 of the Council of Ministers, sent for information.

Sd/-
(Lokesh Kumar Singh)
Secretary (Resources), Department of Finance